'हाईटेक सिटी व मेडी सिटी ऐसी विकसित हों कि नए जयपुर की पहचान बनें'

जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने निर्देश दिया

जयपुर, 6 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर का विकास वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ ही, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए। राज्य सरकार का प्रयास है कि बेहतर एवं सुव्यवस्थित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ जयपुर शहर को उत्कृष्ट मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक इम्प्रूवमैंट प्लान में पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही तथा पॉर्किंग व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर में यातायात के बढ़ते दबाव के मद्देनज़र आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। इसके लिए जेएलएन मार्ग पर स्थित प्रमुख स्थानों को सिग्नल फ्री बनाते हुए सुगम यातायात का प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक इम्प्रूवमैंट प्लान में पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही और पार्किंग व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मुख्य सचिव एवं विभागीय अधिकारियों को इसके लिए फील्ड में मौका-मुआयना करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने हाईटेक सिटी परियोजना के संबंध में कहा कि दिल्ली से जयपुर की निकटता और देश-दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की व्यापक उपस्थिति शहर के लिए विकास एवं निवेश की नई संभावनाएं प्रस्तुत करती है। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हाईटेक सिटी का ऐसा मॉडल विकसित किया जाए, जो आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त हो। उन्होंने कहा कि हाईटेक सिटी और मेडिसिटी का विकास इस प्रकार से हो कि इनका स्वरूप नए जयपुर की पहचान बने।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक देरी एवं लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण सिद्धार्थ महाजन सहित, अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 6 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली, गोवर्धन, धनतेरस और भाईदूज के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रभु श्रीराम का जीवन मर्यादा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और लोककल्याण के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक है। उनके अयोध्या आगमन पर मनाया जाने वाला दीपोत्सव का पर्व हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और निराशा से आशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।

- उन्होंने दीपावली, गोवर्धन, धनतेरस की हार्दिक बधाई दी।

उन्होंने कामना की कि दीपोत्सव का पावन पर्व देश-प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। साथ ही, उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना के साथ त्योहार मनाने तथा विकसित राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनने का आव्हान किया।

महिला आयोग परिसर में शिकायतकर्ता ने आत्महत्या का प्रयास किया

जयपुर, 6 नवम्बर। टोंक रोड स्थित गांधी नगर मोड़ पर महिला आयोग परिसर में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पति के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची एक महिला आत्महत्या करने के इरादे से तीन मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गई। महिला छत की रेलिंग के दूसरी तरफ जाकर कूदने की तैयारी में थी। इसी दौरान एडवोकेट चरणजीत भाटी और फैमिली कोर्ट के कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और सुरक्षित नीचे खींच लिया।

- छत की रेलिंग पर चढ़ी महिला को एडवोकेट व कर्मचारियों ने बचाया।

जानकारी के अनुसार, रेलिंग पर चढ़ी महिला कह रही थी कि कोई उसके पास आया तो वह कूद जाएगी। वह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, न्यायाधीश और मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग कर रही थी। साथ ही प्रेम विवाह निरस्त करने और न्याय दिलाने की बात कह रही थी।

एडवोकेट चरणजीत भाटी ने बताया कि वे फैमिली कोर्ट में प्रवेश कर ही रहे थे, कि उनकी नजर छत की रेलिंग पर चढ़ी महिला पर पड़ी। वे तुरंत सीढ़ियों से छत पर पहुंचे। वहां फैमिली कोर्ट और महिला आयोग के तीन-चार कर्मचारी भी पहुंच गए थे। भाटी ने महिला को बातचीत में उलझाया और मौका मिलते ही उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया। इसके बाद अन्य कर्मचारियों ने भी उसे संभालकर सुरक्षित छत पर खींच लिया।

महिला को फैमिली कोर्ट प्रथम, द्वितीय और तृतीय के न्यायाधीशों के समक्ष पेश किया गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद उसके भाई की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार उसका परिवार उसे मानता है। शादी के बाद वह उत्तर प्रदेश चली गई थी। वहां की पुलिस ने उसे जयपुर महिला आयोग में शिकायत करने की सलाह दी थी। शुक्रवार को जब वह महिला आयोग पहुंची तो कार्यालय पर ताला लगा मिला। इससे वह घबरा गई और निराश होकर आत्महत्या के इरादे से छत पर चढ़ गई।

करोल बाग में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच भी करवाएगी और सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां लोगों की जान को कोई खतरा तो नहीं है।

फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और पुलिसकर्मी इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हैं।

इज़रायल के पूर्व सेना प्रमुख आइसेनकोट को बहुमत का समर्थन मिला

ग्यारह सांसदों वाली अरब पार्टियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर आइसेनकोट को समर्थन का सत्र सौंपा

यरुशलम (इज़रायल), 06 नवंबर। इज़रायल में गुरुवार देर शाम नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। 11 सांसदों वाली अरब पार्टियों के गठबंधन, "ज्वाइंट लिस्ट" के नेताओं ने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रपति को मध्यमार्गी गठबंधन के नेता और पूर्व सेना प्रमुख 66 वर्षीय गादी आइसेनकोट के समर्थन का पत्र सौंप दिया। आइसेनकोट "यशार पार्टी" के नेता हैं। उन्होंने पिछले साल पार्टी बनाई और इस साल चुनाव मैदान में कूदे।

"द यरुशलम पोस्ट" और "द टाइम्स ऑफ इज़रायल" की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह हुए नेसेट (संसद) के चुनाव के बाद उन्हें विपक्षी गुटों और अरब राजनीतिक दलों ज्वाइंट लिस्ट और "राअम" का समर्थन मिलने तस्वीर बदल गई। इनके समर्थन से आइसेनकोट 120 सदस्यों वाली नेसेट में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत के आंकड़े (61 सीट) को पार कर गए। अरब पार्टी राअम के आठ सांसद हैं। चुनाव में आइसेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन के 48 उम्मीद जीते हैं।

- आइसेनकोट ने कहा कि वे इज़रायल को यहूदी राष्ट्र मानते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश चलायेंगे।

देश में सबसे ज्यादा समय 19 वर्ष तक सत्ता में रहे बेंजामिन नेतन्याहू नई सरकार के गठन के लिए आवश्यक बहुमत नहीं जुटा सके। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में उनके गठबंधन को 53 सीटें मिलीं। गुरुवार को नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन में शामिल सात सांसदों वाली पार्टी यूनाइटेड टोरा जूडिज्म (यूटीजेड) ने अलग होने की घोषणा कर दी। इसके बाद समीकरण बदल गए। नेतन्याहू गुट के पास केवल 46 सांसद बचे। यूटीजेड ने फिलहाल नेसेट में अलग बैठने का फैसला किया है।

आइसेनकोट ने कहा कि वह इज़रायल को यहूदी राष्ट्र मानते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश को चलाएंगे। हमास को आतंकी संगठन मानते हुए उसकी सैन्य शक्ति को खत्म किया जाएगा। सेना में भर्ती के लिए नियम बदले जाएंगे।

अमिताभ बच्चन को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ई-मेल भेजा गया था, जिसमें दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल था। उस समय अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि अमिताभ बच्चन को कोई सीधी धमकी नहीं मिली है।

इस घटना के बाद, अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित घर के बाहर हर रविवार को होने वाला, प्रशंसकों से मिलने का उनका कार्यक्रम इस बार अलग रूप में हुआ। वे एक "प्रोटैक्टिव ग्लास शील्ड" के पीछे खड़े थे, और उनके साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे।

इस घटना के बाद, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है। एसोसिएशन ने बॉलीवुड कलाकारों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ये ताजा घटनाएं, 18 अक्टूबर को अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी के बाद मशहूर हस्तियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सामने आई हैं। उक्त गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली थी।

उल्लेखनीय है कि इसी सप्ताह अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी बिश्नोई गिरोह के नाम पर धमकियां मिली हैं। पुलिस अभी इन धमकी भरे ऑडियो संदेशों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

दिल्ली में एक्यूआई 400 पहुँचा, ग्रैप-3 की पाबन्दियां तुरंत लागू हुईं

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिन्तित प्रबन्धन आयोग की उपसमिति ने शुक्रवार शाम को निर्णय लिया

नई दिल्ली, 06 नवंबर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर सख्त कदम उठाते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण कार्यों, वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर आयोग ने यह फैसला लिया है। ग्रैप-3 लागू होने के साथ ही, संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 382 तक पहुंच गया। कई क्षेत्रों में एक्यूआई का स्तर 400 के पार चला गया। प्रदूषण के बढ़ ते स्तर को देखते हुए शुक्रवार शाम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की और ग्रैप 3 की पांबदियों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया।

ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंध में, निर्माण एवं तोड़फोड़ (सीएंडडी) से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध, गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर रोक, निर्धारित क्षेत्रों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर पाबंदी, कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ ाई का विकल्प, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक और अन्य गतिविधियों पर सख्त निगरानी शामिल हैं। इसके अलावा, सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा धूल नियंत्रण और प्रदूषण कम करने के उपायों के कड़ाई से पालन के साथ ही, पहले और दूसरे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे।

कांग्रेस ने अग्निपथ योजना रद्द करने की मांग की

नई दिल्ली, 06 नवंबर। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना रद्द कर नियमित सैनिकों की भर्ती शुरू करने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने 'जय जवान-पार्ट 2' अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत पूरे देश में अग्निवीर सैनिकों की मांगों को उठाया जाएगा।

कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल (रि.) रोहित चौधरी ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने सेना पर अग्निपथ योजना थोपी थी और अब पहले बैच के चार साल पूरे होने पर 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल किया कि अग्निवीरों को स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है।

सिद्धारमैया, पूर्व मु.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी चर्चा की थी।

इस बीच, कथित स्टिंग वीडियो की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस ने शुरुआती तौर पर संकेत दिया है कि वीडियो में किए गए दावे मनगढ़त हैं और जानबूझकर तैयार किए गए हैं।

पुलिस आयुक्त कार्यालय, बेंगलुरु शहर की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस वीडियो को बनाने, रिकॉर्ड करने, अपने पास रखने, एक जगह से दूसरी जगह भेजने और प्रसारित करने के मामले की व्यापक जांच की जा रही है।

इस वीडियो के सामने आने के बाद मीडिया में काफी चर्चा हुई है और जनता के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

पुलिस ने कहा, "अब तक जुटाए गए सबूतों से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वीडियो में दिखाए गए यौन शोषण के आरोप एक मनगढ़ंत और जानबूझकर रची गई कहानी का हिस्सा हैं। जांच के दौरान अब तक दर्ज किए गए बयान और जुटाए गए सबूत वीडियो में दिखाई गई ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करते हैं।"

पुलिस ने यह भी बताया कि वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनसे विस्तार से पूछताछ की गई है। इनमें से कुछ लोगों से एक से अधिक बार पूछताछ की गई।

पुलिस के अनुसार, उनके बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों से प्रथम दृष्टया यही संकेत मिलता है कि वीडियो में शामिल लोगों पर लगाए गए या उनसे जुड़े आरोप "झूठे और मनगढ़ंत" हैं। मामले की जांच अभी जारी है।

पतंजलि की टीम देवी -देवताओं का उपहास उड़ाने वालों पर मुकदमे करेगी

पौड़ी गढ़ वाल, 06 नवंबर। उत्तरांखड के पौड़ी गढ़ वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित मालागांव में आयोजित तीन दिवसीय हर्बल कुंभ, जड़ी-बूटी कृषि मेला एवं श्री धन्वंतरि धाम महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह में योग ऋषि स्वामी रामदेव ने सनातन धर्म और देवी-देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने घोषणा की कि भगवान राम, कृष्ण, हनुमान सहित, अन्य देवी-देवताओं का उपहास करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पतंजलि में विशेष टीम गठित की जाएगी।

भारत में जन्मी नित्या ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी तैयार हैं।

चुनावी मुकाबले में उनका उतरना एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी पूर्व सहयोगी कैरेन बास का समर्थन किया था। नित्या रमण ने कहा कि शहर अब एक "नाज़ुक मोड़" (ब्रेकिंग पॉइंट) पर पहुँच गया है, और नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी।

कैरेन बास पिछले दो दशकों में लॉस एंजलिस की पहली ऐसी मेयर बन गई हैं, जो दोबारा चुनाव जीतने में नाकाम रही हैं। उनका पहला कार्यकाल भीषण पैलिसेड्स आग की घटना से प्रभावित हुआ। यह आग उस समय लगी थी, जब वे देश से बाहर थीं और अग्निशमन विभाग इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं था। आग से हुई भारी तबाही के बाद, बहुत से मतदाताओं के मन में यह पक्का विचार बन गया कि कैरेन बास को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वे इस नुकसान से कभी उबर नहीं पाईं।

- नित्या पहले, डेमोक्रैटिक सोशलिस्ट पार्टी की मुख्य उम्मीदवार कैरेन बास की टीम में थीं। पर, पर्चा भरने की "डैडलाइन" से कुछ समय पहले ही उन्होंने पर्चा दाखिल कर, अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी।

काउंटर इंटैलिजैंस कश्मीर ने 6 क्षेत्रों में छापे मारे

श्रीनगर, 06 नवंबर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) विंग ने शुक्रवार को आतंकी भर्ती मामले के सिलसिले में कश्मीर में छह जगहों पर तलाशी ली। एक अधिकारी ने बताया कि सीआईके की टीमों ने दक्षिण कश्मीर के बडगाम, श्रीनगर, बिजबेहरा और अनंतनाग के मट्टन इलाकों में घरों की तलाशी ली। इसके अलावा पुलवामा जिले के एक गांव में भी तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि यह तलाशी स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में ली गई। अधिकारी ने कहा कि सीआईके श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 07/2023 के तहत दर्ज यह मामला कथित तौर पर चल रहे एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल से जुड़ा है।

'बिना पटाखों वाली दिवाली को जन आंदोलन बनाएं'

नई दिल्ली, 06 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान साफ हवा की पहल को "जन आंदोलन" में बदलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे त्योहारों पर प्रदूषण को केवल अदालती आदेशों या पुलिस की तैनाती के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ ते वायु प्रदूषण को लेकर दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान की।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे स्थानीय नगर पार्षदों को सक्रिय रूप से शामिल करें, ताकि वे नागरिकों से आने वाली दिवाली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे न फोड़ने की अपील कर सकें।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण को अदालत के आदेश या पुलिस की तैनाती से नियंत्रित नहीं कर सकते।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना होगा। जब तक लोग स्वयं जागरूक होकर प्रदूषण फैलाने वाले तौर-तरीकों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव देखना नामुमकिन है।

क्रीमी लेयर का आधार मां-बाप का वेतन नहीं पद होना चाहिये- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण स्टेटस बेस्ड है, न कि पूरी तरह इनकम बेस्ड

नई दिल्ली, 06 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण के मामले में केन्द्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोहराया कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की वेतन से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर से बाहर रखने का निर्धारण माता-पिता की आय के बजाय, उनकी सेवा संबंधी स्थिति और पद के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये फैसला रेट्रोस्पैक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। ग्यारह मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन मामले में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर के मानदंडों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया था।

- अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला रेट्रोस्पैक्टिव या पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण स्टेटस-बेस्ड या पद-आधारित है, न कि पूरी तरह इनकम-बेस्ड... माता-पिता का पद (जैसे ग्रुप ए, बी, सी या डी) क्या है, यह देखना जरूरी है। आमतौर पर माना जाता है कि 8 लाख से अधिक सालाना आय होने पर उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आ जाता है, लेकिन मूल नियमों (1993 ऑफिस मेमोरेंडम) के अनुसार, वेतन और खेती की जमीन से होने वाली आय को इस 8 लाख की गणना से कड़ाई से बाहर रखा गया है।

सीबीएसई की परीक्षायें 16 फरवरी से शुरु होंगी

नई दिल्ली, 06 नवंबर। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड ने 6 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। इसके अनुसार, दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। ऐसे में छात्रों को अपनी परीक्षा की तारीख और विषय के अनुसार तैयारी करने का समय मिल गया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी कक्षा की पूरी डेटशीट देख सकते हैं। इसमें हर विषय की परीक्षा की तारीख और समय दिया गया है।

सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होकर 9 मार्च 2027 तक चलेंगी। इस बार 10वीं के छात्रों को कुल 83 विषयों की परीक्षा देनी होगी। बोर्ड ने सभी विषयों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस दिया

कांग्रेस की केरल इकाई के अधिकारिक अकाउन्ट से चीफ जस्टिस के खिलाफ एक पोस्ट वायरल हुई थी

नई दिल्ली, 06 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन इससे ऊपर नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं है। यह नोटिस सोशल मीडिया पर की गई एक ऐसी पोस्ट को लेकर दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत को निशाना बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक फैसलों की आलोचना की जा सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल डराने-धमकाने या न्याय प्रक्रिया में दखल देने के लिए एक ढ ाल के रूप में नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, यदि वह अदालत के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसने इस मामले में एक वरिष्ठ वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है, जो यह जांच करेंगे कि इस मामले में आपराधिक या दीवानी अवमानना लागू होती है या नहीं। साथ ही, अदालत ने इस मामले में अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से भी सहयोग मांगा है।

- अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, यदि वह अदालत के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिये।

सात राज्यों में मतदाताओं को एक और अवसर मिलेगा

नई दिल्ली, 06 नवंबर। चुनाव आयोग दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होने वाले मतदाताओं को एक बार फिर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दो जगह पर सूचीबद्ध होने के चलते जिन मतदाताओं का नाम काटा है, उन्हें फिर से नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। आयोग ने कहा है कि संबंधित बूथ स्तर के अधिकारी बूथ स्तर के राजनीतिक दलों के एजेंट के साथ मिलकर एक बार फिर छूटे मतदाताओं को शामिल करने के लिए प्रयास करेंगे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908